उस्मान मियां और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

4 अक्टूबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठाकर, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-सिद्धांतों को दोहराया गया-मृत व्यक्ति को चोटें पाई गईं-ठीक से समझाया नहीं गया-अपीलकर्ताओं द्वारा शव को जल्दबाजी में दफनाने का प्रयास-याचिका झूठी-अपीलकर्ता फरार, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां-हालांकि बचाव याचिका का झूठ दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त लिंक प्रदान करता है।

मृतक की शादी अपीलार्थी नं.1 से हुयी थी. अपीलकर्ता 2 और 3 उसके सौतेले बेटे थे और वे शादी से खुश नहीं थे। शादी के दो महीने बाद मृतक ने जानकारी भेजना शुरू कर दिया कि अपीलकर्ता उसे परेशान और प्रताड़ित करते थे और उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे। घटना से कुछ दिन पहले, सूचना देने वाले का छोटा भाई आर. एच. (पी. डब्ल्यू.-3) उससे मिला था जब उसने उससे उसे ले जाने के लिए कहा था नहीं तो

अपीलकर्ता उसे मार देंगे। अपनी बहन की मौत की सूचना मिलने पर पीडब्लू-10, पीडब्लू-4, पीडब्लू-8, पीडब्लू-3, उसकी बहन और पीडब्लू-7 के साथ नासिरपुर गांव में अपीलार्थियों के घर गए और मृतक का शव घर के दक्षिणी बरामदे में एक खाट पर पड़ा देखा। शरीर कपड़े से ढका हुआ था। उस समय तक दोनों गाँवों, अर्थात् छतरघाट और नासिरपुर के कई लोग वहाँ जमा हो चुके थे। गर्दन पर खरोंच और नीले रंग के दाग के निशान और दाहिने पार्श्व क्षेत्र पर काले दाग दिखाई दे रहे थे। उक्त निशानों को देखने के बाद एक संदेह पर कि मृतक की हत्या उसके पति और उसके सौतेले बेटों, यानी वर्तमान अपीलार्थी द्वारा की गई थी, एक शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता अपने घर से फरार थे। वे शव को दफनाने के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे लेकिन पुलिस दल को देखकर वे भाग गए।

अभियुक्त ने मुकदमे का इस प्रभाव से बचाव किया कि मृतक घटना की तारीख से 3 से 4 दिन पहले से बीमार थी और बहुत कमजोर हो गई थी। वह उस रात कुएं से पानी लेने आई थी और नीचे गिरने से घायल हो गई, बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। निचली अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों को उन परिस्थितियों पर भरोसा करके दोषी पाया जिन्हें उजागर किया गया था, यह मानते हुए कि डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य पर अविश्वास करने वाले आरोपों को मानने के लिए परिस्थितियाँ पर्याप्त थीं।

अपील में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमजोरी नहीं है।

इस न्यायालय में अपील करने पर, यह तर्क दिया गया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है कि भले ही परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, वे परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला नहीं बनाते हैं और इसलिए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, वे अपीलकर्ता संख्या 1 के रूप में आरोप साबित नहीं करते हैं।

प्रत्यर्थी-राज्य ने निचली अदालतों के फैसले का समर्थन किया और कहा कि निचली अदालतों के तर्कसंगत और सुविचारित फैसलों ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को स्थापित किया है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. किसी अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध को किया गया प्रतीत होना चाहिए और सभी परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों की जांच करके प्रत्यक्ष नेत्र साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए जिन्होंने इसको होते देखा था। अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। फैक्टम प्रोबेंडम

के प्रमुख तथ्य को अप्रत्यक्ष रूप से फैक्टम प्रोबेंस से लिए गए कुछ निष्कर्षों के माध्यम से साबित किया जा सकता है, जो कि प्रमाणिक तथ्य हैं। इसे अलग तरह से रखने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुद्दे के बिंदु पर प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य शामिल हैं जो मुद्दे में तथ्य के साथ इतने निकटता से जुड़े हुए हैं जो एक साथ परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिनसे प्रमुख तथ्य के अस्तित्व का कानूनी रूप से अनुमान लगाया जा सकता है या माना जा सकता है। [27-बी, सी]

2. जहाँ कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का अनुमान केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित करना होगा और उन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाले जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। जहाँ मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहाँ परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता नकारात्मक हो और अपराधों को किसी भी उचित संदेह से परे घर लाया जा सके। [27-डी, ई, एफ, जी]

हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 1063; एराडू बनाम हैदराबाद राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316; अरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर. (1983) एस. सी. 446; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी, AIR (1985) SC 1224; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR (1987) SC 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR (1989) SC 1890 और भगत राम बनाम पंजाब राज्य, AIR (1954) SC 621, संदर्भित।

3. निचली अदालत ने विस्तृत रूप से चिकित्सा साक्ष्य पर विचार किया है और पाया है कि डॉक्टर की राय पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निहित वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष के साथ संगत नहीं थी। एक महत्वपूर्ण विशेषता, जिस पर नीचे की अदालतों द्वारा सही ध्यान दिया गया है, वह यह है कि हालांकि शुरू में आरोपी व्यक्ति मौजूद थे, जब पुलिस के समक्ष शिकायत की गई थी कि मामला हत्या का था न कि आकस्मिक मृत्यु का, तो आरोपी व्यक्ति फरार हो गया है। एक अन्य विशेषता, जिस पर नीचे की अदालतों द्वारा सही ध्यान दिया गया है, वह यह है कि शव को जल्दबाजी में दफनाने का प्रयास किया गया था। अपीलार्थी मृतक के घर के निवासी थे। बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य, जिनसे इस दलील की पुष्टि करने के लिए पूछताछ की गई थी कि मृतक कुएँ के पास गिर गया है, को खारिज कर दिया गया है। हालांकि बचाव याचिका का झूठ मानने

योग्य नहीं है। आरोप, यह अभियोजन पक्ष के आरोपों को साबित करने के लिए अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। निचली अदालत द्वारा उजागर की गई परिस्थितियाँ, आरोप को मानने के लिए पर्याप्त हैं जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ सही ठहराया गया है। [30-सी, डी, ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 587/1999

आपराधिक अपील संख्या 424/1986 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 7.8.98 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से यू. यू. ललित, ज़की अहमद खान और इरशाद अहमद।

उत्तरदाताओं की ओर से बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निर्णय द्वारा:

अरिजीत पासायत, जे.

तीन अपीलार्थियों ने पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए वर्तमान अपील दायर की, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 32 के साथ पठनीय अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि और 1983 के सत्र परीक्षण संख्या 145 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गया, बिहार द्वारा लगाए

गए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया। यह इंगित किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो गई है और इसलिए जहाँ तक उसका संबंध है, अपील समाप्त हो जाती है।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष का बयान इस प्रकार है -

गाँव नासिरपुर के कलामुद्दीन और अलाउद्दीन मियां ने इश्तियाक अहमद (पीडब्लू-10) और अभियोजन पक्ष के अन्य सदस्यों को गाँव छतरघाट में अपने घर पर सुबह 6.3.1981 पर सूचित किया कि सैस्ता खातून (जिसे इसके बाद 'मृतक' कहा जाता है) की मृत्यु हो गई है। उसे बताया गया कि कुछ मेहमान मृतक के घर आए थे; उन्हें खाना परोसने के बाद वह सोने चली गई। आधी रात को उसके रोने की आवाज सुनी गई और बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई थी।

उपरोक्त जानकारी मिलने पर इश्तियाक अहमद (पीडब्लू-I0) (मामले के मुखबिर) अपने पिता अनवररुल हक (पीडब्लू-4), मां नफीसा खातून (पीडब्लू-8), भाई राशिद हुसैन (पीडब्लू-3), बहन (जांच नहीं की गई) और चाची हसमत खातूम (पीडब्लू-7) के साथ गांव नासिरपुर में अपीलार्थियों के घर के लिए रवाना हुए। उन्होंने साइस्ता खातून का शव घर के दक्षिणी बरामदे में एक खाट पर पड़ा देखा। शरीर कपड़े से ढका हुआ था। उस समय तक दोनों गाँवों, अर्थात् छतरघाट और नासिरपुर के कई लोग वहाँ

जमा हो चुके थे। वे फुसफुसाते हुए बोल रहे थे कि सैस्ता खातून को मार दिया गया है। मृतक की अंतिम झलक पाने के लिए उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया गया था। गर्दन पर खरोंच और नीले रंग के दाग के निशान और दाहिने जननांग के क्षेत्र पर काले रंग के दाग दिखाई दे रहे थे। अभियोजन पक्ष को उक्त निशान देखने के बाद संदेह हुआ कि मृतक की हत्या उसके पति और उसके सौतेले बेटों यानी वर्तमान अपीलार्थियों ने की थी।

इश्तियाक अहमद (पीडब्लू-10) ने शाम 6 बजे अपीलार्थियों के घर के प्रांगण में जो फरदेयान रखा था, उसमें उन्होंने आगे उल्लेख किया कि मृतक की शादी अपीलार्थी नं. 1 उस्मान मियां से 8 मार्च, 1980 को हुयी थी। अपीलकर्ता अबरार अहमद और इफ्तेखार अहमद, जो उसके सौतेले बेटे थे, शादी से खुश नहीं थे। शादी के दो महीने बाद मृतक ने यह जानकारी भेजना शुरू कर दिया कि अपीलार्थी उसे परेशान और प्रताड़ित करते थे। एक-दो बार उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना से दस दिन पहले राशिद हुसैन (पीडब्लू-3), सूचना देने वाले का छोटा भाई उससे मिला था जब उसने उससे उसे ले जाने के लिए कहा ताकि अपीलकर्ता उसे ना मार सकें। मुखबिर ने आगे उल्लेख किया कि अपीलार्थी अपने घर से फरार थे। वे शव को दफनाने के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे लेकिन पुलिस दल को देखकर वे भाग गए।

उपरोक्त के आधार पर फरदबेयान चंदौती पी. एस. केस No.34/81 6.3.1981 को दर्ज किया गया था। जाँच की गई और उसके पूरा होने पर अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने बेगुनाही का अनुरोध किया और मुकदमे का सामना किया।

अभियुक्त व्यक्तियों, जैसा कि प्रतिपरीक्षा की प्रवृत्ति और अभियोजन पक्ष के गवाहों को दिए गए सुझावों और डी. डब्ल्यू. I, शुएल अहमद के साक्ष्य से स्पष्ट है, ने इस प्रभाव पर रुख अपनाया कि मृतक घटना की तारीख से 3 से 4 दिन पहले से बीमार थी और बहुत कमजोर हो गई थी। वह दुर्भाग्यपूर्ण रात में कुएं से पानी लेने आई थी और जब वह नीचे गिर गई तो उसे चोटें आईं, वह बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। अपने आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की। इश्तियाक अहमद (पीडब्लू-10) मुखबिर और मृतक का भाई था। राशिद हुसैन (पीडब्लू-3) उनके भाई और पीडब्लू 4 और 8, अनवररुल हक और नफीसा खातून क्रमशः उनके पिता और माता थे। डॉ. कपिलदेव प्रसाद (पीडब्लू-9) द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 313 के तहत आरोपी व्यक्तियों की जांच के दौरान उन्होंने घर के बरामदे में शव की उपस्थिति से इनकार किया।

निचली अदालत ने उजागर की गई परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य पर अविश्वास करते हुए कहा कि आरोप मान लेने के लिए परिस्थितियां पर्याप्त थीं।

अपील में उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तार से जांच की और आक्षेपित आदेश द्वारा यह माना कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमजोरी नहीं थी।

अपील के समर्थन में, श्री यू. यू. ललित ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। भले ही परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, वे परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला नहीं बनाते हैं और इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनके अनुसार, किसी भी स्थिति में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, वे अपीलार्थी नंबर 1 उस्मान मियां के संबंध में आरोप साबित नहीं करती हैं।

दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निचली अदालतों के फैसले का समर्थन किया और कहा कि नीचे की अदालतों के तर्कसंगत और सुविचारित फैसलों ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के

अपराध को स्थापित किया है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में लगाई गई परिस्थितियाँ इस प्रकार हैंः

(1) सैस्ता खातून अपीलार्थी नं. 1 उस्मान मियां उर्फ घासो मियां की दूसरी पत्नी और अपीलार्थी नं. 2 इफ्तेखार मियां अहमद और अपीलार्थी नं. 3 अबरार अहमद की सौतेली माँ थी। वास्तव में यह स्वीकार किया जाता है।

(2) सैस्ता खातून की मृत्यु उनके पति के घर पर हुई। यह भी स्वीकार किया जाता है।

(3) मृत शरीर अपीलार्थी के घर के बरामदे में एक खाट पर रखा हुआ पाया गया।

(4) जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौके पर पहुंचे तो शव कपड़े से ढका हुआ था।

(5) शरीर पर चोटों के निशान थे।

(6) अपीलार्थी जल्दबाजी में शव को दफनाना चाहते थे।

(7) सैस्ता खातून के साथ अपीलार्थियों, विशेष रूप से अपीलार्थी संख्या 2 और 3 द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।.

(8) मृत्यु के समय वह दो महीने की गर्भवती थी।

(9) एक पुरुष बच्चे के संभावित जन्म से अपीलार्थी संख्या 2 और 3 की विरासत की सीमा प्रभावित होने की संभावना थी।

(10) अपीलार्थी विशेष रूप से, अपीलार्थी सं. 2 और 3 का मृतक को मारने का बहुत मजबूत मकसद था।

(11) जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अपीलकर्ता फरार पाए गए।

इन परिस्थितियों में से कुछ सामान्य प्रकृति की थीं। परिस्थितियाँ (5) (6) और (11) महत्वपूर्ण हैं। परिस्थितियाँ 7,9 और 10 अपीलार्थी संख्या 2 और 3 के संबंध में अतिरिक्त कारक हैं।

तथ्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने से पहले यह कहा जा सकता है कि किसी अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध करते देखा गया हो और सभी परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों की जांच करके प्रत्यक्ष नेत्र साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए जिन्होंने इसका कार्य देखा था। अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। मुख्य तथ्य या तथ्यात्मक प्रोबैंडम को अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यात्मक प्रोबन्स, यानी साक्ष्य तथ्यों से लिए

गए कुछ निष्कर्षों के माध्यम से साबित किया जा सकता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुद्दे के बिंदु पर प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य शामिल हैं जो मुद्दे में तथ्य के साथ इतने निकटता से जुड़े हुए हैं कि वे परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिनसे प्रमुख तथ्य के अस्तित्व का कानूनी रूप से अनुमान लगाया जा सकता है या माना जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का निष्कर्ष केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं। [देखें हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 1063, एराडू बनाम हैदराबाद राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316, एरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर. (1983) एस. सी. 446, यू. पी. राज्य. बनाम सुखबासी, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 1224, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 350 और अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1890]। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित करना होगा और उन

परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाले जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 621 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से लिए गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता को नकारात्मक बनाए और किसी भी उचित संदेह से परे अपराधों को साबित करे।

हम सी. चेंगा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य, (1996) 10 एस. सी. सी. 193 में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया हैः

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

पदला वीरा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 79 में यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

(2) वे परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर बिना किसी कारण के इंगित करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(3) परिस्थितियों को, कुल मिलाकर, इतनी पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था किसी और के द्वारा नहीं; और

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।"

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (1992) आपराधिक एल. जे. 1104 में यह बताया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है वह यथोचित रूप से दो निष्कर्ष निकालने में सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक 'विल्स'(अध्याय VI) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रूप से निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया हैः (1) किसी भी कानूनी निष्कर्ष के आधार के रूप में कथित तथ्यों को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए और फ़ैक्टम प्रोबैंडम से जुड़े उचित संदेह से परे होना चाहिए; (2) सबूत का भार हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाता है; (3) सभी मामलों में, चाहे वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, सबसे अच्छा सबूत पेश किया जाना चाहिए जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है; (4) अपराध के निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए, दोषारोपण करने वाले तथ्य अभियुक्त की

निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए; और (5) यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने के अधिकार का हकदार है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा 1952 में निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी से किया जाना चाहिए।

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 343 में यह इस प्रकार देखा गया थाः

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पहली बार में पूरी तरह से स्थापित होने चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं

छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (1984) एस. सी. 1622 में बाद के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के दौरान, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी कि श्रृंखला पूरी हो गई है और अभियोजन पक्ष में कमी की दुर्बलता को झूठे बचाव या याचिका से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तें, दोषसिद्धि से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती हैं, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए। वे इस प्रकार हैंः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया ही जाना चाहिए या करना चाहिए और नहीं किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए; और

(5) सबूत की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचली अदालत ने विस्तृत रूप से चिकित्सा साक्ष्य पर विचार किया है और पाया है कि डॉक्टर की राय ईमानदार नहीं होते हुये पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निहित वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष के साथ असंगत थी। एक महत्वपूर्ण विशेषता, जिस पर नीचे की अदालतों द्वारा सही ध्यान दिया गया है, वह यह है कि हालांकि शुरू में आरोपी व्यक्ति मौजूद थे, जब पुलिस के समक्ष शिकायत की गई थी कि मामला हत्या का था न कि आकस्मिक मृत्यु का, तो आरोपी व्यक्ति फरार हो गया है। एक अन्य विशेषता, जिस पर नीचे की अदालतों द्वारा सही ध्यान दिया गया है, वह यह है कि शव को जल्दबाजी में दफनाने का प्रयास किया गया था। अपीलार्थी मृतक के घर के निवासी थे। बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य, जिनसे इस दलील की पुष्टि करने के लिए पूछताछ की गई थी कि मृतक कुएं के पास गिर गया है, को खारिज कर दिया गया है, और हमारे विचार में यह सही है। हालाँकि बचाव पक्ष की याचिका का झूठ

आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह अभियोजन पक्ष के आरोपों को साबित करने के लिए अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। कर्नाटक राज्य बनाम लक्ष्मणैया, [1992] सप्लीमेंट 2 एस. सी. सी. 420 में, घटना की तारीख से उसकी गिरफ्तारी तक आरोपी के फरार होने का आचरण एक महत्वपूर्ण परिस्थिति मानी गई थी।

निचली अदालत द्वारा उजागर की गई परिस्थितियाँ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरोप को मानने के लिए पर्याप्त हैं जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ सही ठहराया गया है।

उपर्युक्त के आधार पर, हम निचली अदालत द्वारा किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं, जो किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देते हैं।

अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

वी. एम.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।